

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4330

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

05 चैत्र, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 योजना के तहत प्रगति

4330. श्री डगुमल्ला प्रसादा राव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित आवेदनों की राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) स्वीकृति के वर्ष सहित इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और सीएफसी की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (घ) ईएमसी योजना के अंतर्गत बिक्री योग्य/पट्टे पर दिए जाने योग्य भूमि क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए तैयार कारखानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को देश भर के 16 राज्यों से 31 आवेदन [21 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और 10 सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)] प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 1986.25 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित 4,127 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले नौ (9) ईएमसी और एक (1) सीएफसी को देश भर के 7 राज्यों में अनुमोदित किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण एमईआईटीवाई की वेबसाइट, <<https://www.meity.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/modified-electronics-manufacturing-clusters-emc-2-0-scheme>> पर उपलब्ध है।

भारत सरकार स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहन बनाना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाना है। भारत सरकार ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने तथा भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक ईउ पाय/पहल लागू की है।

इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9,52,000 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ('सीएजीआर') है। अब हम एक ऐसे चरण में पहुँच गए हैं जहाँ भारत में उपयोग किए जा रहे 99.2%

मोबाइल हैंडसेट भारत में ही बनाए जाते हैं और वित्त वर्ष 2022-23 में हम मोबाइल निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में हम मोबाइल आयात करने वाले देश थे, जब भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन कालगभग 74% आयात किया जाता था। विवरण अनुबंध में दिया गया है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) उत्पन्न हुए हैं।

अनुबंध

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2014-15	190,366	38,263
2015-16	243,263	39,064
2016-17	317,331	39,980
2017-18	388,306	41,220
2018-19	458,006	61,908
2019-20	533,550	82,929
2020-21	554,461	81,822
2021-22	640,810	116,895
2022-23	822,350	189,934
2023-24	952,000	241,157

राशि: करोड़ रुपये में